

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 42/25

GCMS NO 2025/76

विद्याल सिंह पुत्र भजन जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरुठ जिला करौली

अपीलांत



बनाम

हकिम सिंह पुत्र हजारी जाति माली निवासी शेरपुर तहसील सूरुठ जिला करौली
कमला

3. जयलाल पिसरान लोहरे
4. समंदर
5. मोहन
6. नरेश पिसरान श्यामा जाति न माली निवासीयान शेरपुर तहसील सूरुठ जिला करौली
7. तहसीलदार तहसील सूरुठ जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 336/22 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 27.3.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा


अभिभाषक रेस्पो0 श्री पुरुषोत्तम गोयल

दिनांक 19.12.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की आर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 27.3.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरुठ मे वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। मौके पर खातेदारान ने उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। बाहमी बंटवारा अनुसार वादी ने उक्त आराजी के पूर्व खातेदार भरसी,श्रीमन व फुलबुंती पिसरान घीसोली से उनके उत्तरी तरफ के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है एवं उसी हिस्से पर खरीद के दिनांक आज तक वादी काबिज एवं दलील है एवं उत्तरी हिस्से का हवाला भी वादी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे भली प्रकार से अंकित है। इसी प्रकार उक्त आराजीयात का बहामी बंटवारे के आधार पर विधिवत बंटवारा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी के पास ज्यादा जमीन है इसलिए उस पर काश्त नही करने देगे तब वादी ने प्रतिवादीगण से विधिवत बंटवारा कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इकार कर दिया। प्रतिवादीगण जबरन वादी के हिस्से पर कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि आराजी खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरुठ मे वादी के 1/2 हिस्से की अलग खातेदारी कायम की जावे। मौका कमिश्नर से बंटवारा स्कीम प्राप्त की जावे। फाईनल डिकी किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिया। जिसका दावा तकमील मुहायदा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा बउनवानी सोहन सिंह बनाम प्रेम मु0न0 51/22 न्यायालय अति0सिविल जज हिण्डौन सिटी के यहाँ विचाराधीन है। जो जैरकार है। जिसका इल्म वादी/रेस्पो0 को भली भाँति है। फिर भी वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त सभी तथ्य पक्षकार दावा पेश किया है जो मेटेबल नहीं है। उक्त सारे तथ्य वाद जबाब व तनकीयात कायम किये जाते, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो जबाब दावा लिया गया तथा बिना जबाब दावे के ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अहम भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात पर समंदर, महेन्द्र, नरेश पिसरान श्यामा का मौके पर कब्जा नहीं है तथा बिना कब्जे के आधार पर दावा मेटेबल नहीं है। इसलिए उक्त प्राथमिक डिक्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सारी प्रक्रिया को ताक मे रखकर निर्णय व डिक्री पारित की है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरुठ मे रेस्पो0 संख्या 1 वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। मौके पर खातेदारान ने उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। बाहमी बंटवारा अनुसार वादी ने उक्त आराजी के पूर्व खातेदार भरसी, श्रीमन व फुलवती पिसरान घीसोली से उनके उत्तरी तरफ के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है एवं उसी हिस्से पर खरीद के दिनांक से आज तक वादी काबिज एवं दलील है एवं उत्तरी हिस्से का हवाला भी वादी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे भली प्रकार से अंकित है। इसी प्रकार उक्त आराजीयात का बहामी बंटवारे के आधार पर विधिवत बंटवारा कराने के अधिकारी होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से की आराजी मे दखल अंदाजी कर कब्जे मे महरूम करने के कारण बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि उक्त भूमि को सोहन सिंह द्वारा पूर्व मे जरिये एग्रीमेंट खरीद किया है। जबकि इस प्रकार का कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहाँ तक जबाब दावे का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा जानबूझकर जबाब दावा पेश नहीं किया है तथा सहमति देकर वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री करने का निवेदन किये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया गया है। इसी प्रकार जहाँ तक दूसरे वाद का प्रश्न है तो अपीलाधीन वाद की आराजीयात भी भिन्न है तथा इस वाद की आराजी भिन्न है तथा पक्षकार भी समान नहीं है। इस प्रकार दोनो दावो को कसोलिडेट नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

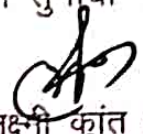
उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी/रेस्पो0 द्वारा आराजी खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरुठ बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र मे श्यामा की पुत्रीयो को पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधुपुर

न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से होती है। इसी प्रकार अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपीलांत/प्रतिवादी न0 1 निहाल सिंह द्वारा एक अन्य दावा तत्काल एवं स्थाई निषेधाज्ञा निहाल सिंह बनाम प्रेम दिनांक 6.5.22 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है जबकि हस्तगत अपील से संबंधित वाद दिनांक 21.11.22 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकार उनवानी दावा निहाल सिंह बनाम प्रेम हस्तगत अपीलाधीन निर्णय से पूर्व का है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि दोनों दावों को कंसोलिडेट कर दोनों दावों पर विनिश्चयक किया जाकर एक साथ निर्णय पारित करना चाहिए था। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं कर पूर्व दावे के पश्चात पेश किये गये दावे का निस्तारण पहले कर दिया गया है जो न्याय संगत है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को जबाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बिना जबाब दावे के ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जबकि बंटवारे के बाद में सहखातेदार से जबाब दावा प्राप्त किया जाकर दावा एवं जबाब दावा अनुसार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण में श्यामा के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर तथा एक अन्य दावा निहाल सिंह बनाम प्रेम को कंसोलिडेट कर हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांत रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 336/22 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.3.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है आपके न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन दावा बउनवानी निहाल सिंह बनाम प्रेम व अपीलाधीन दावे को कंसोलिडेट किया जाकर तथा श्यामा के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए जबाब दावा प्राप्त किया जाकर हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जावे। यहाँ यह तथ्य समाचीन है कि प्रकरण में पुनः साक्ष्य लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के यहाँ दिनांक 13.01.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी कान्त बालोत)
सजस्य अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर